क्या करेंगे कचरा कंप्यूटरों का?

यदि एरिज़ोना स्टेट विश्वविद्यालय के एरिक विलियम्स द्वारा किया गया एक हालिया अध्ययन सही है तो अगले कुछ सालों में कंडम कंप्यूटरों की संख्या में भयानक वृद्धि होने वाली है और इसमें से अधिकांश वृद्धि चीन, भारत व अन्य विकासशील देशों में होगी।*एन्वायर्मेंट साइन्स टेक्नॉलॉजी* नामक पत्रिका में प्रकाशित इस अध्ययन में अनुमान व्यक्त किया गया है कि 6-8 साल के अंदर विकसित देशों की अपेक्षा विकासशील देश कहीं अधिक कंप्यूटर खारिज करेंगे और 2030 तक विकासशील देशों द्वारा फेंके जाने वाले कंप्यूटरों की संख्या विकसित देशों से 2-3 गुना हो जाएगी। फिलहाल दुनिया भर में प्रति वर्ष करीब 18 करोड़ कंप्यूटर कचरे में फेंके जा रहे हैं और यदि वृद्धि की यही रफ्तार जारी रही तो 2030 से प्रति वर्ष 1 अरब कंप्यूटरों का कचरा इकट्ठा होगा।

विलियम्स का कहना है कि इन अनुमानों का अर्थ यह है कि यदि विकसित देशों से विकासशील देशों को जो पुराने कंप्यूटर रीसायक्लिंग के लिए भेजे जाते हैं, वे न भी भेजे जाएं, तो भी खुद विकासशील देशों में कंप्यूटर-कचरे का बड़ा जखीरा होगा।

कंप्यूटर का रीसायक्लिंग मुश्किल होने का साथ-साथ, काफी खतरनाक भी है। जैसे सर्किट बोर्ड और तारों से धातुएं प्राप्त करने के लिए कई खतरनाक रसायनों का उपयोग होता है। तांबा प्राप्त करने के लिए किया यह जाता है कि तारों का इंसुलेशन जला दिया जाता है। इस प्रक्रिया में कई हानिकारक रसायन पैदा होते हैं। सर्किट बोर्ड्स से सोना व अन्य कीमती धातुएं प्राप्त करने के लिए पूरे बोर्ड को नाइट्रिक अम्ल और सायनाइड से धोया जाता है। जो अम्ल और सायनाइड्स बचते हैं उन्हें ठिकाने लगाने का कोई निरापद तरीका नहीं होता।

रीसायक्लिंग के ऐसे तौर-तरीके कई सवाल खड़े करते हैं। जैसे आजकल कंप्यूटर उद्योग पर काफी दबाव है कि वह अपनी मशीनों में पर्यावरण मित्र पदार्थों का उपयोग करे। मगर यदि रीसायक्लिंग के तरीके उपरोक्त जैसे रहे तो अधिकांश प्रदूषण कंप्यूटरों के पदार्थ से नहीं बल्कि रीसायक्लिंग की प्रक्रिया से पैदा होगा।

विलियम्स कहते हैं कि विकासशील देशों में बढ़ती कंप्यूटर खपत और रीसायक्लिंग के इन तरीकों का मिला-जुला असर यह होगा कि चाहे जितने व्यापारिक प्रतिबंध लगाएं और कंप्यूटरों को चाहे जितना पर्यावरण के लिए हानिरहित बनाएं, अंततः ये हानिकारक ही साबित होंगे।

और विलियम्स के आंकड़ों में सिर्फ कंप्यूटरों का हिसाब लगाया गया है। मोबाइल फोन्स, एमपीथ्री प्लेयर्स, फैक्स मशीनों, प्रिंटर्स वगैरह को भी जोड़ेंगे तो समस्या और विकराल नज़र आएगी।

वैसे कचरे के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सम्बंधी बेसल संधि पर काम करने वाले कहते हैं कि फिलहाल तो समस्या यही है कि विकासशील देशों में रीसायक्लिंग के लिए आने वाला अधिकांश कंप्यूटर कचरा विकसित देशों से ही आ रहा है। इसलिए भविष्य की चिंता में आज को नहीं भूलना चाहिए। उनका मत है कि कंप्यूटर कचरे को विकासशील देशों में झोंकने पर सख्त रोक होनी चाहिए। विलियम्स इससे सहमत हैं मगर उनका मत है कि हमें इसके साथ-साथ विकासशील देशों में रीसायक्लिंग की प्रक्रिया को निरापद बनाने की दिशा में भी काम करना होगा। ***(स्रोत फीचर्स)***